

13-7-2010



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2010/आषाढ़ 10, 1932

No. 181]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2010/ASADHA 10, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2010

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत।

फा. सं. 15/4/2010-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 39/1/99-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। अंतिम जाँच परिणाम के आधार पर दिनांक 17-1-2006 की अधिसूचना सं. 3/2006 के तहत राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

यतः सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार यदि पाटनरोधी शुल्क पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी सं. 2006 का 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

3. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद सोडियम नाइट्राइट है जो कि ऑक्सीकारक एवं अवकारक अभिकर्मक दोनों ही है। यह एक सफेद स्वादाय पाउडर होता है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भेषज उद्योगों, रंगाई उद्योगों, स्नेहकों, निर्माण संबंधी रसायनों, रबड़ ब्लोइंग एजेंट, ऊष्मा अंतरण लवणों, माँस प्रसंस्करण आदि में होता है। सोडियम नाइट्राइट के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री अमोनिया है जिसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में उच्च तापमान पर नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट प्राप्त करने के लिए कॉस्टिक सोडा में नाइट्रस ऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। उत्पाद गंधहीन और जल में घुलनशील होता है। इस जाँच के निर्णायक समीक्षा होने के कारण इसमें वही उत्पाद शामिल हैं जो मूल जाँच में शामिल थे। सोडियम नाइट्राइट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की शीर्ष सं. 2834.10 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और संबद्ध जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

4. प्रक्रिया

I) इस जाँच से यह निर्धारण किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क की समाप्ति या उसमें परिवर्तन या दोनों ही किए जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है :-

- i. इस समीक्षा में दिनांक 01.12.2005 की अधिसूचना सं. 39/1/1999-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे। इस समीक्षा जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।
- ii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2006- मार्च, 2007, अप्रैल, 2007- मार्च, 2008, अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 तथा जाँच की अवधि शामिल होगी।
- iii. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

II) सूचना प्रस्तुत करना

घरेलू उद्योग द्वारा शुल्क का अधिरोपण जारी रखने की आवश्यकता का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग हेतु आवेदन) में इस आशय से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि पहले से लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 243

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकारों हेतु उसका एक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

III) समय सीमा

घरेलू उद्योग से सूचना प्रस्तुत होने पर, सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हों, को इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को लिखित में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिनके पते उपलब्ध न हों, भी घरेलू उद्योग के आवेदन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रयोजनार्थ आवेदन के अगोपनीय रूपांतर को सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

IV) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध

तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2010

(Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty on imports of Sodium Nitrite originating in or exported from China PR.

F. No. 15/4/2010-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Sodium Nitrite (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country). The final findings notification of the Authority was published vide notification No. 39/1/1999-DGAD dated 01st December, 2005. On the basis of the findings, anti dumping duty was imposed on the imports of the subject goods from subject country by the Department of Revenue vide notifications No. 3/2006 – Customs dated 17.01.2006.

2. Initiation of Sunset Review

WHEREAS in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the antidumping duties imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, Hon'ble Delhi High Court in WP No 16893 of 2006 has held that sunset review is mandatory. Therefore, pursuant to the stated orders of the Hon'ble High Court, the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance with section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules, to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. Product under Consideration

Product under consideration is Sodium Nitrite, which is an oxidizing as well as reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceutical industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing etc. The major raw material for production of Sodium Nitrite is Ammonia which is converted into nitrous oxide at high temperature in presence of catalysts. The nitrous oxide

is further absorbed in caustic soda to get sodium nitrite. The product is odourless and soluble in water. This being a sunset review, investigation covers the products covered in the original investigation. Sodium Nitrite is classified under heading 2834.10 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

4. Procedure

I) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both:-

- i. The review will cover all aspects of Notification 39/1/1999-DGAD dated 01.12.2005. The countries involved in this review investigation are China PR.
- ii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April 09 to 31st March 2010. The injury investigation period will however cover the periods April'2006-March'07, April'2007-March'2008, April'2008-March'2009 and the POI.
- iii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

II) Submission of Information:

The Domestic industry is required to submit information on the prescribed *pro forma* (Application for Domestic Industry) and information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both substantiating the need for continuation of duty within forty days (40 days) of issue of this notification.

The exporters in the subject country, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned, would be addressed separately to submit the relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 243,
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

2524 G17/10-2

III) Time Limit:

On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from the date of application from Domestic industry. For this purpose, non-confidential version of the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

IV) Inspection of Public File:

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by the interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendation to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority